जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

उदयपुर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 32 संख्याः 102 प्रभात उदयपुर, गुरुवार 13 फरवरी, 2025 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

'केन्द्रीय सरकार ने रक्षा मंत्रालय के कायदे-कानून में तब्दीली की, अडानी ग्रुप सोलर प्लांट के लिये'

सीमा से 10 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार के ''सिविल कंस्ट्रक्शन'' की इजाज़त नहीं होती है, बॉर्डर पर टैंक आदि मशीनों को ''फ्री मूवमैंट'' की सुविधा देने के लिये

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और विवादास्पद अडानी समूह के निकट सम्बंधों का एक और खुलासा हुआ है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने गौतम अडानी के विश्व के सबसे बड़े नवीकरणीय एनर्जी पार्क को मंजूरी देने के लिए रक्षा प्रोटोकॉल में ढील दी है। यह पार्क गुजरात के खावदा में बन रहा है जहां कच्छ के रन में भारत-पाक सीमा के एक किलोमीटर दायरे में सोलर पैनल और विंड टरबाइन लगाए जाएंगे।

प्रोटोकॉल में छेड़छाड़ से अन्य देश जैसे चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान व म्यामांर के लिए भी सीमा पर ऐसे निर्माण करने का रास्ता साफ हो जाएगा।

रक्षा विशेषज्ञों का सवाल है कि ''क्या एक बिज़नैस ग्रुप का हित राष्ट्रीय सुरक्षा से भी बड़ा है?'' वे कहते हैं कि स्वतंत्र भारत में देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा समझौता पहली बार किया गया है।

नीति में परिवर्तन से यह सवाल उठ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान से कोई हमला होता है, जैसा पहले हो चुका है, तो भारत इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां कैसे संचालित करेगा।

कच्छ का 445 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र गुजरात सरकार ने अडानी की कम्पनी को लीज़ पर दिया है।

गार्जियन का दावा है कि उसके पास ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे रक्षा मंत्रालय द्वारा सिक्युरिटी प्रोटोकॉल के संशोधन का पता चलता है ताकि अडानी के प्रोजैक्ट को मदद दी जा सके। अडानी की प्रधानमंत्री मोदी से निकटता को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी अक्सर निशाना साधते हैं।

पाकिस्तान सीमा पर 10 किलोमीटर दायरे में, जो गांव और सड़के हैं, उनके अलावा कोई अन्य निर्माण करने की अनुमति नहीं है। गुजरात से लेकर जम्मू-कश्मीर के बीच भारत और पाकिस्तान के 3,323 किलोमीटर लम्बा बॉर्डर साझा करते हैं।

गार्जियन के अनुसार दस्तावेज दिखाते हैं कि सुरक्षा प्रोटोकॉल में ढील देने के लिए भाजपा ने उच्चतम स्तर पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- पर, जब अडानी ग्रुप को खावड़ा (गुजरात) में 445 वर्ग किलोमीटर भूमि, सोलर व विंड एनर्जी प्लांट लगाने के लिये दी गई तो रक्षा मंत्रालय के कानून-कायदों में परिवर्तन करके, सीमा से एक किलोमीटर दूर ही ''सिविल कन्स्ट्रक्शन'' की इजाज़त दे दी गई।
- यह खबर प्रमुखता से लंदन के जाने-माने अखबार ''द गार्डियन'' में छपी है तथा अखबार ने दावा किया है कि उसके पास पूरे कागज़ात व दस्तावेज मौजूद हैं, अपनी खबर की सत्यता प्रमाणित करने के लिये।
- अखबार ने यह भी दावा किया है कि पहले खावड़ा में 230 वर्ग किलोमीटर भूमि, राज्य सरकार की कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन को सोलर एनर्जी प्लांट लगाने के लिये ''लीज़'' पर दी गई थी। पर, मई 2023 में सरकारी कॉर्पोरेशन को आदेश देकर यह भूमि वापस ली गई तथा जुलाई 2023 को यह भूमि अडानी ग्रुप को दी गई।
- अडानी ग्रुप ने इस प्लांट में पैदा सोलर एनर्जी को राज्य सरकारों को बहुत भारी दामों पर बेचने के लिये अनुबंध किये तथा अमेरिकी सरकार द्वारा अडानी ग्रुप पर भारी रिश्वत देने का अभियोग पत्र दाखिल किया, सोलर एनर्जी को भारी दामों पर राज्य सरकारों को बेचने के लिये।

प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत कांग्रेस में लौटे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 फरवरी। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी चार साल तृणमूल कांग्रेस में रहने के बाद बुधवार को कांग्रेस में पुन: शामिल हो गए।

पूर्व लोकसभा सदस्य को पार्टी के राज्य मुख्यालय में कांग्रेस सदस्यता दी गई। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी गुलाम अहमद मीर वहाँ मौजूद थे।

- कांग्रेस की सदस्यता लेते हुए अभिजीत ने कहा चार साल पहले कांग्रेस छोड़कर गलती की थी।

सन् 2021 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के अपने फैसले पर खेद व्यक्त करते हुए मुखर्जी ने कहा, ''मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, कांग्रेस छोड़ना सही नहीं था। यह कांग्रेस और राजनीति में मेरा दूसरा जन्मदिन है।''

यह दावा करते हुए कि देश की राजनीति में कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है, उन्होंने कहा, ''केवल कांग्रेस ही सभी लोगों को साथ लेकर चलती है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या सम्प्रदाय का हो।'' मुखर्जी ने कहा कि उन्होंने पिछले साल जून में कांग्रेस में फिर से शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन विभिन्न राज्य चुनावों के कारण अब यह संभव हो सका है।

उन्होंने, जुलाई 2024 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के चार साल बाद कांग्रेस में वापसी की है।

रिज़र्व बैंक को आशा है कि महंगाई नहीं बढ़ेगी

रिज़र्व बैंक ने इस आशा से ही ब्याज दर घटायी है, पर, क्या यह आकलन एकदम सही है?

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 फरवरी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी हालिया मौद्रिक नीति में, केन्द्रीय बजट के तुरंत बाद ब्याज दरों में थोड़ी कमी की है। ब्याज दर 6.50 से 6.25 प्रतिशत कर दी गई है।

यह कोई भारी कमी नहीं है। लेकिन इससे एक उम्मीद और मानसिकता बनती है। खासकर क्योंकि यह पांच सालों में पहली कटौती है। तीन मुख्य प्रश्न जो सामने आए, वो थे, क्या ब्याज दर को और कम किया जाएगा, कीमतों को क्या दिशा मिलनी चाहिए, और क्या अर्थव्यवस्था मजबूत गति से बढ़ती रहेगी।

रिज़र्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने जवाब दिया कि भविष्य में बैंक ब्याज दरों पर फैसला उस डेटा के आधार पर करेगा जो आने वाले समय में मिलेगा और जिस तरह से अर्थव्यवस्था व्यवहार करेगी। तो सवाल यह है कि अब से लेकर मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की अगली बैठक तक अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव हो सकता है?

गवर्नर के बयान से ऐसा लगता है कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि कीमतें स्थिर रहेंगी। क्या यह अनुमान वाजिब और युक्तिसंगत है? खाद्य पदार्थों की कीमतों को छोड़कर, मूल्य वृद्धि काफी हद तक कम रही है। सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं और इसकी उम्मीद कम है कि इन कीमतों में स्थिरता आएगी।

यह मुख्यत: इसलिए है क्योंकि फल और सब्जियों की मांग बढ़ रही है, क्योंकि, आय में सुधार हो रहा है। बढ़ती आय के साथ, पैरिशेबल आइटम्स (जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं) का उत्पादन उतना नहीं बढ़ा है। इसके अलावा इन वस्तुओं के उचित परिवहन के लिए फसल के बाद की सुविधाओं में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- उदाहरण के लिये, फल व सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, सर्दियों में भी।
- आय में बढ़ोतरी होने से फल व सब्जियों की खपत बढ़ी है, पर, इन दोनों का उत्पादन इस अनुपात में नहीं बढ़ा है और न ही फल-सब्जियों को खाने के टेबल पर शीघ्रतम समय में पहुँचाने के लिए ट्रांस्पोर्टेशन के इन्फ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हुई है।
- ऑयल (पैट्रोलियम) के दामों में भी गत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- वित्त मंत्री ने इन्फ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि में भारी राशि लगाई है, पर, अभी भी प्राइवेट सैक्टर, औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिये मशीनों आदि की क्षमता नहीं बढ़ा रहे। शायद उनको अभी पूर्ण विश्वास नहीं है कि डिमांड बढ़ेगी और डिमांड की पूर्ति के लिये वो अपनी फैक्टरियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाए।
- पर, वित्त मंत्री की यह आशा की कंज़्यूमर गुड्स की खपत बढ़ेगी, आधारहीन नहीं। इन्फ्रास्ट्रक्चर में सरकार द्वारा पूँजी लगाने से तथा बजट में, मध्यम वर्ग के हाथों में इन्कम टैक्स घटाकर ज्यादा पैसे पहुँचाने का कुछ न कुछ अच्छा असर तो होगा ही।

संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना में राजस्थान को 4102 एमसीएम पानी मिलेगा

केन्द्रीय जल शक्ति सचिव ने राजस्थान व मध्य प्रदेश को, संशोधनों को समाहित कर डीपीआर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये

जयपुर, 12 फरवरी। संशोधित पीकेसी (पार्वती-कालीसिंध-चम्बल) लिंक परियोजना की डीपीआर को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार को नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय की सचिव श्रीमती देबाश्री मुखर्जी की अध्यक्षता में अधिकारियों की अहम बैठक हुई।

इसमें राजस्थान एवं मध्यप्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय जल विकास अभिकरण को प्रस्तुत डीपीआर पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में सचिव जल शक्ति मंत्रालय ने दोनों राज्यों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवश्यक संशोधनों को समाहित करते हुए आगामी 15 दिवस में डीपीआर प्रस्तुत करें।

परियोजना में राजस्थान को कुल 4102 एमसीएम जल उपलब्ध होगा। इसमें 522.80 एमसीएम पुनर्चक्रित जल शामिल है। कुल 4102 एमसीएम जल में से 1744 एमसीएम पेयजल, 205.75 एमसीएम उद्योगों, 1159.38 एमसीएम जल नए सिंचित क्षेत्र, 615.43 एमसीएम जल पूर्व निर्मित बांधों में जल अपवर्तन के लिए, 108 एमसीएम जल भू-जल पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जा सकेगा। शेष 270 एमसीएम जल का उपयोग खराब मानसून के समय में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं डीपीआर के अनुसार अन्य विकास कार्यों में उपयोग में लिया जा सकेगा।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार प्रदेश में पेयजल और सिंचाई के लिए जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में संशोधित पीकेसी (पार्वती-कालीसिंध-चम्बल) एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके जरिए राजस्थान के 17 जिलों के लगभग सवा 3 करोड़ लोगों और 2.51 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हो सकेगी। पूर्व में स्थापित 1.52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में भी सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी उपलब्ध हो सकेगा।

- पार्बती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना को अंतिम रूप देने के लिये हुई बैठक में राजस्थान के लिये 4102 एमसीएम जल निर्धारण किया गया। राजस्थान के हिस्से के जल का, पेयजल, उद्योगों, नये सिंचित क्षेत्र, पूर्व निर्मित बाँधों में जल अपवर्तन, भूजल पुनर्भरन तथा खराब मानसून के समय पेयजल उपलब्ध कराने के लिये विभिन्न मात्रा में जल निर्धारण तय किया गया।

मुम्बई में जी.बी.एस. संक्रमण से पहली मौत

मुंबई, 12 फरवरी। महाराष्ट्र में गुलियन-बेरी सिंड्रोम (जीबीएस) के संदिग्ध मरीजों की संख्या 200 के पार पहुंच गई है। वहीं, मुंबई में इस बीमारी से पहली मौत के साथ ही राज्य में एक महीने में जीबीएस से संदिग्ध तौर पर 8 लोगों की जान जा चुकी है। पुणे में जीबीएस के सबसे ज्यादा मरीज हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार पुणे क्षेत्र में जीबीएस के संदिग्ध और पुष्टि किए गए मामलों की संख्या 203 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 203 मामलों में से 176 में जीबीएस का इलाज किया जा रहा है। इसमें से 52 मरीज आईसीयू में है, तथा 20 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। पुणे महानगरपालिका क्षेत्र में 41, ग्रामीण इलाकों से आए 94 मरीजों के अलावा पुणे ग्रामीण क्षेत्र के 31 सहित अन्य जिले के 8 मरीजों का अस्पतालों में जीबीएस का उपचार चल रहा हैं।

- महाराष्ट्र में इस संक्रमण से 8 मरीज मर चुके हैं। संक्रमितों की संख्या 200 के पार पहुंच गई है।

बंगलौर की मैट्रो का किराया दोगुना हुआ

भाजपा व कांग्रेस, दोनों इस वृद्धि के लिये एक दूसरे पर आरोप लगाने में जुटी हैं

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 फरवरी। बेंगलुरु मेट्रो के किराए में भारी वृद्धि ने सिद्धारमैया सरकार की छवि और बैंगलोर की जनता के बीच सरकार की लोकप्रियता को भारी नुकसान पहुँचाया है, जो मैट्रो किराया वृद्धि पर नाराज हैं। इसे कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के लिए बहुत बुरा प्रचारक ही जा रहा है।

भाजपा के लिए, यह दृश्य आदर्श है। भाजपा ने कांग्रेस सरकार को एक जनविरोधी और लापरवाह संस्था के रूप में पेश करने में कोई समय नहीं गंवाया और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सभी सावधानियों और अर्थशास्त्र को नज़रअंदाज़ कर राज्य को उस स्थिति में पहुंचा दिया, जहां आम लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

यह कथानक कांग्रेस पर चिपक रहा है और सरकार बैकफुट पर है, सरकार जो बचाव पेश कर रही है उस पर लोग विश्वास करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, भले ही यह तथ्यों के आधार पर सही हो।

यह सही है, बेंगलुरु मैट्रो में किराया वृद्धि बहुत ज्यादा है, कुछ मामलों में पहले से लगभग दोगुनी और स्वाभाविक रूप से, भाजपा ने इस मुद्दे पर सरकार को जमकर निशाने पर लिया है और कहा है कि राज्य सरकार लोगों को हर तरीके से लूट रही थी ताकि अपनी वोट-बटोरने वाली मुफ्त योजनाओं के लिए धन जुटा सके।

भाजपा की आलोचना का जवाब देते हुए, राज्य के परिवहन मंत्री के रामलिंग रेड्डी ने कहा कि मैट्रो किराया वृद्धि जो दो दिन पहले लागू हुई थी, में राज्य सरकार की बिल्कुल भी कोई भूमिका नहीं थी। किराया वृद्धि केंद्रीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे मैट्रो कॉर्पोरेशन द्वारा तय और लागू की गई थी। रेड्डी ने कहा कि भाजपा हमेशा किसी भी चीज़ का श्रेय लेने में सबसे आगे रहती है, लेकिन जब दोष लेने का समय आता है तो वे दूसरे पर डाल देती हैं।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यह बात शुरु की, उन्होंने कहा कि बेंगलुरु मैट्रो केंद्र, राज्य सरकार और मैट्रो कॉर्पोरेशन का संयुक्त ऑपरेशन है और इसके सी.ई.ओ. केंद्रीय शहरी विकास सचिव भी हैं और किराए में वृद्धि का निर्णय उन अधिकारियों द्वारा लिया गया था, जिन पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण है।

सिद्धारमैया ने भाजपा नेताओं के खिलाफ अभियान छेड़ा और कहा भाजपा नेता हमेशा मैट्रो परियोजना का श्रेय लेने में आगे रहते हैं और किराया वृद्धि पर सार्वजनिक आक्रोश होने पर कांग्रेस को दोषी ठहराते हैं। भाजपी नेता झूठ व आधा सच फैला रहे हैं ताकि 5 साल बाद हुई किराया वृद्धि पर तथ्यों को तोड़मरोड़ सकें।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- भाजपा, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है कि सस्ती लोकप्रियता के लिये ''रेवड़ियाँ'' बांटने के कारण राज्य सरकार ने ''इकॉनमी'' को तहस-नहस कर दिया है तथा आम आदमी से मैट्रो किराया वृद्धि जैसी स्कीमों से पैसा लूट कर, ''रेवड़ियाँ'' बाँटने के लिये पैसे इकट्ठे कर रही है और यहीं से मैट्रो का किराया दोगुना करने की दुखंतिका की शुरुआत हुई है।
- कांग्रेस का कहना है कि किराया वृद्धि में उसकी कोई भूमिका नहीं है। बैंगलोर मैट्रो केन्द्रीय सरकार का प्रोजैक्ट है तथा भारत सरकार के नगरीय विकास सचिव इस प्रोजैक्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं तथा सरकार और अफसरों से मिलजुल कर मैट्रो का किराया बढ़ाने का निर्णय लिया है।
- यह भी सच है कि 2017 में जब मैट्रो का किराया निश्चित किया गया था तब मैट्रो 42.30 किलोमीटर चलती थी, पर, अब 175.55 किलोमीटर लंबा है, मैट्रो का नैटवर्क। अतः, किराया तो बढ़ना ही है।

मुख्य पुजारी आचार्य सत्येन्द्र दास का निधन

लखनऊ, 12 फरवरी। अयोध्या में रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। बुधवार सुबह 7 बजे लखनऊ पीजीआई में उन्होंने आखिरी सांस ली। 3 फरवरी को ब्रेन हेमरेज के बाद उनको अयोध्या से लखनऊ रैफर किया गया था।

पीजीआई निदेशक डॉक्टर आर.के. धीमान ने बताया, डॉक्टरों की निगरानी में लगातार उनका इलाज चल रहा था। ब्रेन स्ट्रोक के अलावा सत्येंद्र दास को कई अन्य बीमारियां भी थीं। काफी प्रयास के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।

आचार्य सत्येंद्र दास का पार्थिव शरीर अयोध्या के सत्य धाम गोपाल मंदिर आश्रम में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। आचार्य सत्येंद्र दास के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने शोक जताया।

'फोन टैपिंग आज की हो या पहले की, निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए'

पायलट ने कहा, आरपीएससी पर हाई कोर्ट की टिप्पणी बहुत कुछ बयां कर रही है

जयपुर, 12 फरवरी। राजस्थान में फोन टैपिंग के मुद्दे पर छिड़े सियासी घमासान के बीच जहां डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भाजपा की ओर से मिले नोटिस का जवाब देते हुए अपनी गलती मान ली है,वहीं दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने कहा है कि यह कोई छोटा-मोटा मुद्दा नहीं है। यह गंभीर अपराध है। विशेष रूप से जब मंत्री खुद कह रहे हैं कि उनका फोन टैप हो रहा है।

पायलट ने कहा कि अगर कांग्रेस के लोग कहें तो आप कहोगे कि यह राजनीति से प्रेरित है। अब इस पर क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी घटना चाहे आज की हो या पहले की, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

पायलट बोले, हर गलती सजा मांगती है। कोई गलती करेगा तो सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस सरकार के समय लगे फोन टैपिंग के आरोपों पर उन्होंने कहा कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। सच सामने आ जाएगा।

पायलट ने कहा कि सरकार के एक मंत्री हैं, जिन्होंने सार्वजनिक मंच पर आरोप लगाया कि उनका फोन टैप हो रहा है। वो खुद कह रहे हैं कि उनका फोन टैप हुआ है। उन पर उनका दल नोटिस देकर जवाब मांगने की कार्रवाई करता है। यह उनका अंदरूनी मामला है।

पायलट ने कहा कि हाईकोर्ट ने आरपीएससी को लेकर जो टिप्पणी की है, वह अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। आरपीएससी नौजवानों का भविष्य तय करने वाली संस्था है। हमने पहले भी कहा है कि आरपीएससी की कार्यप्रणाली पूरी तरह से कम्प्रोमाइज़्ड हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि ईआरसीपी को लेकर पहले राजस्थान को जितना पानी मिलना चाहिए था। अब सामने आया है कि नए एमओयू में उतना पानी नहीं मिल रहा है। इस पर भी सरकार को सदन में जवाब देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि समरवता में हुई घटना के बाद हमने न्यायिक जांच की मांग की थी। हमने कहा था कि प्रशासनिक और पुलिस जांच से सच सामने नहीं आएगा। न्यायिक जांच से ही पीड़ितों को न्याय मिल सकता है, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि पीड़ितों के साथ न्याय हो।

कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने जयपुर में अपने आवास पर राजस्थान में फोन टैपिंग के मुद्दे पर मीडिया से वार्ता की।

- उन्होंने कहा कि नये एमओयू में राजस्थान को पहले से कम पानी मिल रहा है। सरकार को विधानसभा में इस पर जवाब देना चाहिये।
- समरावता की घटना पर पायलट ने कहा, ''हमने पहले कहा था कि प्रशासनिक और पुलिस जाँच से सच सामने नहीं आयेगा, न्यायिक जाँच से ही पीड़ितों को न्याय मिल सकता है।

भाजपा ने दिल्ली की हारी हुई सीटों पर मंथन किया

नयी दिल्ली, 12 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली प्रदेश की बुधवार को चुनाव प्रबंध समितियों की समीक्षा बैठक हुयी, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया गया और हारी हुई विधानसभा सीटों का आकलन किया। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी प्रभारी बैजयंत जय पांडा की अध्यक्षता में हुयी इस बैठक पार्टी के सह प्रभारी अतुल गर्ग, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद प्रवीण खंडेलवाल, सांसद बांसुरी स्वराज, सांसद रामवीर सिंह बिधुड़ी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- भाजपा की दिल्ली की चुनाव प्रबंध समितियों ने बैठक में चुनाव जीत के लिए कार्यकर्ताओं का आभार जताया गया।